(b) and (c) Decisions for conversion of loans into equity will be taken by public financial institutions in industrial cases after considering the circumstances of each case.

Review of Letters of Intent/Licences issued to 75 Large Houses

4266 SHRI BHOGENDRA JHA Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to refer to the reply given to Starred Question No 56 on 15th November, 1972 regarding review of licences and letters of intent issued during 1970 71 and 1971 72 and state

(a) the particulars of licences who have been warned, or whom final extension has been given or extension refused or whose licences have been revoked or cancelled, and

(b) whether the position has been or is proposed to be reviewed with regard to the progress made in cases of Letters of Intent or Licences given to the 75 large houses named by the Monopolies Commission if so, the result thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) (a) Particulars of licenses who have been warned or to whom final extension has een given/refused are not generally disclosed The particulars of licences revoked or cancelled are published regularly in the 'Weekly Bulletin of Industrial Licences Import Licences and Export Licences' the weekly 'Indian Trade Journal' and the monthly 'Journal of Industry and Trade' Copies of these publications are supplied regularly to the Parliament Library.

(b) The progress made in cases of letters of intent and licences given to large Houses is reviewed as in other cases, in the manner stated in the reply given to Starred Question referred by the Hon Member.

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को दिये गये ऋणों का गबन

4267. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को 6 करोड रुपये का ऋण दिया था, और

(ख) क्या संघ के विभिन्न केन्द्रों में 50 लाख रु० का गबन किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को ऋण दिया था जिसमें से 5 46 करोड रुपये की राशि 31–3–1972 को संघ पर बकाया थी ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का विकेन्द्रीकरण

4268. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के निदेशक मण्डल ने 5 अक्टूबर, 1972 को हुई अपनी बैठक में अपना विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया है,

(ख) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ श्रमिक संघ ने इस निर्णय का विरोध किया है तथा निदेशक मण्डल को भंग करने तथा संघ को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिये जाने की मांग की है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?